

अमेरिका में जनभावना इज़रायल-ईरान युद्ध में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ

इकॉनमिस्ट/यू गव के सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत जनता अमेरिकी सेना के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ है, केवल 16 प्रतिशत जनता अमेरिका के हस्तक्षेप के पक्ष में है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 जून। इजरायल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका में इकोनॉमिस्ट/यूगव के एक नए सर्वेक्षण में अमेरिकी जनता की स्पष्ट राय नज़र आई है, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इजरायल-ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया है। इसके विपरीत, केवल 16 प्रतिशत लोग अमेरिकी हस्तक्षेप के पक्ष में हैं। यह परिणाम अमेरिकी जनता में युद्ध को लेकर बढ़ती उदासीनता को दर्शाता है, जो पिछले दो दशकों में मध्य पूर्व में खबौंते सैन्य अभियानों और इस समय घरेलू राजनीति में चल रही उथल-पुथल से उपजी है।

यह भावना कोई क्षणिक मनोदशा नहीं, बल्कि अमेरिकी जनमत में लंबे

- इराक व अफगानिस्तान में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वर्षों युद्ध चला, इन युद्धों से परेशान अमेरिकावासी, अब किसी दूसरे देश में जाकर अमेरिका लड़े, इस बात से तंग आ गए हैं।
- विशेषकर “मिडिल ईस्ट” में वे अमेरिकी सेना का सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहते, क्योंकि यह भावना घर कर गई है कि जब भी अमेरिका हस्तक्षेप करता है, युद्ध और लम्बा हो जाता है तथा नतीजा पूर्णतया अमेरिका के पक्ष में हो, ऐसा नहीं होता।
- अमेरिका की जनता, विशेषकर, ईरान के विरुद्ध युद्ध में उतरने के खिलाफ है। क्योंकि ईरान की ओर से “प्रॉक्सी वॉर” लड़ने के लिए कई जगह के लोग तैयार हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, इराक के शिया समर्थक तथा यमन के हाउथी। अतः संभावना यह बनती है कि युद्ध शीघ्र व्यापक रूप धारण कर लेगा, जैसा वियतनाम में हुआ था, जहाँ अमेरिका लम्बे व अनिर्णित युद्ध में फंस गया था।
- अमेरिका की युवा पीढ़ी में यह भावना जोरों से उभरी है कि कूटनीति व युद्ध को रोकना और भड़कने न देना, बेहतर नीति है।

समय से चल रहे बदलाव का हिस्सा है। इराक और अफगानिस्तान में वर्षों तक

चले युद्ध के बाद, सभी अमेरिकन चाहे वे किसी भी राजनैतिक रुझान के हों,

दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस बदले की भावना से पकड़ेगी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे : सचिन पायलट

शनिवार सुबह राजस्थान युनिवर्सिटी में परीक्षा दे रहे छात्रनेता निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने शनिवार को पत्रकारों से रूबरू होकर राजस्थान युनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी और संगरिया (हनुमानगढ़) के विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने की निंदा की। पायलट ने कहा कि “पुलिस, प्रशासन और सरकार अगर बदले की भावना से किसी को पकड़ती है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार यह बात रखना चाहती है कि, जो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार का इस्तेमाल करके अगर किसी की बात को दबाना चाहते हैं, तो इसको मैं गलत मानता हूँ।”

नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग खिताब जीता

पेरिस, 21 जून। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.16 मीटर का श्रे किया और जर्मनी के जुलियन वैबर को पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम किया।

नीरज ने बताया कि वह डायमंड लीग में 90 मीटर के पार फेंकने की कोशिश में थे, लेकिन रन-अप तेज हो

- दो बार के ओलंपिक विजेता नीरज ने जर्मनी के जुलियन वैबर को हराकर यह जीत हासिल की है।

जाने के कारण वह अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उन्होंने ओलंपिक्स डॉट काम से कहा मैं आज 90 मीटर से ज्यादा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रन-अप बहुत तेज था और मैं कंट्रोल नहीं कर सका। फिर भी डायमंड लीग जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी समय बाद खिताब हासिल हुआ है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल ने खुहड़ी के धोरों में योग किया

उन्होंने तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की व बीएसएफ जवानों से मुलाकात की

जैसलमेर, 21 जून (नि.सं.)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पर्यटन मानचित्र में लोकप्रिय, खुहड़ी के रेतीले धोरों पर आयोजित हुआ। शहर से करीब 45 किमी दूर खुहड़ी के धोरों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थितजनों को योग कर निरोग रहने का सन्देश दिया और फिट रहने का संकल्प दिलाया। जैसलमेर विधायक छोटसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला प्रमुख प्रतापसिंह, कलेक्टर प्रतापसिंह सहित आर्मी, एयरफोर्स, व सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे खुहड़ी के रेतीले टीलों पर समारोह में शामिल हुए।

इससे पहले शुक्रवार रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी जैसलमेर की 2 दिवसीय यात्रा पर प्राचीन गढ़ीसर तालाब पर विधि विधान से पूजा अर्चना व मंगल गंगा आरती की।

- जैसलमेर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल खुहड़ी में योग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ आर्मी, एयर फोर्स के जवानों तथा सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया।
- मुख्यमंत्री भजनलाल ग्यारह सौ वर्ष पुराने किशनगढ़ फोर्ट भी गए। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने उन्हें कोर्ट के स्थापत्य व सामरिक महत्व की जानकारी दी।

खुहड़ी सैण्ड ड्यून्स पर मुख्यमंत्री सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के साथ योगाभ्यास किया। जयपुर से आए योग प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास और योग की विभिन्न क्रियाएं करवाईं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को ही भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित तनोट माता मंदिर में दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शौर्य की धरा पर मां तनोट राय का भव्य और

सुंदर मंदिर बनेगा और 200 कमरों का विश्राम गृह भी बनेगा। तनोट यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ फोर्ट भी गए और 1100 वर्षों से अधिक प्राचीन किशनगढ़ फोर्ट के स्थापत्य और सामरिक महत्व की जानकारी ली। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने इस फोर्ट के इतिहास एवं सामरिक महत्व के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तनोट माता मंदिर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने मतदान की वैबकास्टिंग सार्वजनिक करने से इन्कार किया

नयी दिल्ली, 21 जून। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों की वेब-कास्टिंग के रिकार्ड को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराये जाने की मांग को मतदाताओं की निजता की दृष्टि से एक जोखिम भरा मुद्दा बताया है और कहा है कि इसका उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदान की वेबकास्टिंग की नयी

- चुनाव आयोग ने कहा, इससे मतदाताओं की निजता को खतरा हो सकता है।

व्यवस्था आंतरिक उपयोग के लिए की है। इसका उद्देश्य मतदान केंद्र की गतिविधियों के प्रबंध को सुचारु रखना है। वेबकास्टिंग के रिकार्ड को किसी चुनाव आयोग के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश पर तो न्यायालय के विचारधीन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को देना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध होगा।

आयोग के एक सूत्र ने कहा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 जून। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति एक नाजुक एवं संकटपूर्ण मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जिससे वरिष्ठ राजनयिकों और वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों में चिंता की लहर दौड़ गई है। ईरान-इजरायल संकट के तेजी से बिगड़ते हालात को संभालने में रणनीतिक समझ और स्पष्टता की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की

आलोचना बढ़ती जा रही है।

एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त राजनयिक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए, एक प्रमुख भू-राजनीतिक चुनौती के सामने, दिशाहीन होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “नई दिल्ली ने अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता की

‘ईरान, भारत का पुराना आजमाया हुआ मित्र है’

सोनिया गांधी का मानना है कि कई बार यू.एन. में भारत के खिलाफ मानवाधिकार हनन के बारे में आलोचनात्मक प्रस्ताव लाने का प्रयास हुआ है, ईरान ने ये प्रस्ताव “ड्रॉप” करवाये हैं

- सोनिया गांधी की सोच है कि अब गाज़ा में भारी बमबारी व जान-माल का भारी नुकसान हुआ है तथा ईरान पर भी मिसाइल व प्लेन्स व ड्रोन्स का हमला कूटनीति के स्थापित तौर तरीकों के पूर्णतया खिलाफ है।
- अतः भारत को इस मौके पर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुखरित होकर अपनी बात कहनी चाहिए।

स्थिरता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए किया गया। ऐसी कार्रवाइयों केवल अस्थिरता बढ़ाएंगी और आगे के संघर्ष की ज़मीन तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच के कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक संकेत दे रहे थे, जो इसे और भी अधिक पीड़ादायक बनाता है। इस वर्ष अब तक पाँच दौर की वार्ताएँ हो चुकी थीं, और जून में छठा दौर प्रस्तावित था। मार्च 2025 में, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने कांग्रेस में स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा है, और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 2003 में परमाणु कार्यक्रम का निलंबन कर दिया था। उसके बाद से इसे फिर शुरू करने की अनुमति नहीं दी है।

सोनिया गांधी ने कहा कि यह याद रखना जरूरी है कि वर्तमान इजरायली नेतृत्व, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, शांति को कमजोर करने और कट्टरवाद को बढ़ावा देने का एक लंबा और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। उनकी सरकार का लगातार अवैध बस्तियों का विस्तार, अतिराष्ट्रवादी गुटों के साथ गठबंधन करना और दो-राष्ट्र समाधान में बाधा डालना न केवल फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा को बढ़ाता है, बल्कि पूरे क्षेत्र को लगातार संघर्ष की ओर धकेलता है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि नेतन्याहू ने 1995 में नफरत की आग इतनी बढ़ाई की उसकी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्या कर दी गई, जिससे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वाकई में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति लड़खड़ा रही है?

कांग्रेस के शासन में पले-बढ़े भारत के पुराने कूटनीतिज्ञ, इसी सोच में रंगे हुए हैं

- इन लोगों का मानना है कि भारत ने अपनी पुरानी विदेश नीति, जो सामरिक दृष्टि से स्वतंत्र सोच पर आधारित थी, त्याग दी है।
- भारत की यह विदेश नीति, रिएक्टिव, “शॉर्ट साइटेट्ड” दृष्टिकोण पर आधारित है तथा अमेरिका से प्रभावित है। इस परिवर्तन से भारत को खास लाभ नहीं हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसने भारत की विश्वसनीयता को ठेस पहुँचायी है।
- इन पुराने कूटनीतिज्ञों का यह भी कहना है कि वॉशिंगटन व तेल अवीव के नज़दीक जाकर, उनका पक्ष लेकर भारत ने “मिडिल ईस्ट” में अपने पुराने साथियों, मित्रों का विश्वास खोया है।
- विदेश नीति के इन जानकारों का इस लय में यह भी मानना है कि भारत पहले अपने सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था तथा शांति और कूटनीति के पक्ष में बोलता था, बिना किसी के दबाव में आकर।
- ये विशेषज्ञ पुरानी विदेश नीति का गुणगान तो करते हैं, पर, यह भूल जाते हैं कि भारत एक “मेजर प्लेयर” है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपनी आर्थिक सफलता व सफल कूटनीति के कारण।

परंपरा को त्याग दिया है और अमेरिका केन्द्रित तात्कालिक सोच वाली नीति को

अपनाया है।” उनके अनुसार, इस बदलाव से भारत को कोई ठोस लाभ

नहीं मिला है, बल्कि इससे उसकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्राम विकास अधिकारी से रिकवरी पर रोक लगाई

जयपुर, 21 जून। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली की मंडरायल पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निकाली गई 3.70 लाख रुपए की रिकवरी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और स्थानीय जिला परिषद के मुख्य

- सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायतीराज के प्रमुख सचिव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब मांगा।

कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य लेखराज तोषावड़ा ने यह आदेश बनवारी लाल की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि विकास कार्यों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)